

## चागोस द्वीप विवाद के समाधान में भारत की मदद चाहता है इंग्लैंड

### सन्दर्भ

ब्रिटेन के विदेश सचिव ने भारत से उम्मीद जताई है कि वह हिंद महासागर में मौजूद 'चागोस द्वीपसमूह' को लेकर अमेरिका इंग्लैंड और मॉरीशस के बीच जारी विवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वदिति हो कि पिछले साल मॉरीशस ने इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने की धमकी दी थी।

### क्यों है विवाद?

- वर्ष 1965 में मॉरीशस को आज़ाद करने के बाद ब्रिटेन ने हिंद महासागर में मौजूद चागोस द्वीपसमूह को मॉरीशस से अलग कर दिया था। हालाँकि, मॉरीशस आज भी इस द्वीप पर अपना अधिकार जताता है।
- 1966 में अमेरिका ने ब्रिटेन से एक समझौता किया था, जिसके तहत अगले 50 वर्षों तक यानी 2016 तक उसे नरिबाध रूप से डिएगो गार्सिया पर सैन्य गतिविधियों के संचालन की छूट मलि गई थी। इस समझौते के साथ ही अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ मलिकर इस द्वीपसमूह पर वायु और नौसैनिकि बेड़ा स्थापति कर दिया। ज्ञात हो कि डिएगो गार्सिया चागोस द्वीपसमूह का ही एक हस्सिा है।
- वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने समुद्री नयिमों के तहत इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि वर्ष 2010 में द्वीपसमूह के आसपास ब्रिटेन द्वारा बनाया गया समुद्री संरक्षति क्षेत् (जसिमें डिएगो गार्सिया सम्मलिति नहीं है) इस अभसिमय के तहत ब्रिटेन के दायतिवों से तर्कसंगत नहीं है।

### चागोस द्वीपसमूह का भारत के लयि महत्त्व

- हिंद महासागर के बीच स्थति डिएगो गार्सिया द्वीप का रणनीतिक महत्त्व इसलयि है क्यौंकि यह द्वीप अपनी भौगोलिक स्थति और चक्रवातीय क्षेत् से बाहर है। वदिति हो कि अमेरिका ने डिएगो गार्सिया स्थति अपने सैन्य बेड़ों का इस्तेमाल इराक और अफगानसितान के युद्ध में बहुतायत से किया था।
- भारत के लयि डिएगो गार्सिया में अमेरिकि फौजों की मौजूदगी तब खासा सरिदरद साबति हुई थी, जब 1971 में भारत-पाक युद्ध के दौरान दुनिया में शीतयुद्ध का माहौल बना हुआ था। उस दौर में अमेरिका अपने हतियों के मद्देनजर खुलकर पाकसितान के समर्थन में आ गया था। इसी दौर में हमारे देश के रणनीतिकारों में यह राय बनी थी कि डिएगो गार्सिया में अमेरिकि सैन्य बेड़ों की उपस्थति भारत से लयि भारी खतरा है।
- ब्रिटेन का कहना है कि चागोस द्वीपसमूह का मुद्दा वहाँ रहने वाले लोगों के अनुसार तय होना चाहयि न कि मॉरीशस या कसिी अन्य देश की इच्छा के अनुसार, वही इस मामले में भारत का रुख यह है कि इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र महासभा में ले जाने का नरिणय मॉरीशस सरकार को करना होगा और ब्रिटेन इसे सकारात्मक कदम मानता है।